भारत में फलों और सब्जियों का उत्पादन

1684. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विश्व में फलों का तीसरा सबसे बड़ा और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है ;

(ख) यदि हां, तो 1993–94 में प्रत्येक प्रमुख मद का कुल कितनी मात्रा में और कुल कितने भू-क्षेत्रफल में उत्पादन हुआ ;

(ग) विश्व के अन्य देशों की तुलना में प्रमुख फलों तथा सब्जियों का उत्पादन स्तर कितना है ;

(घ) क्या बीजों की अधिक पैदावार वाली किस्मों तथा कृमि-प्रतिरोधी किस्मों के विकास में धीमी प्रगति रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुन्धिद नेताम) : (क) खाद्य एवं कृषि संगठन उत्पादन वर्ष पोथ (1992) के अनुसार भारत विश्व में क्रमशः ब्राजील और चीन के बाद फलों तथा सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

(ख) तथा (ग) यद्यपि 1993–94 के आंकड़े अभी प्राप्त होने हैं, फिर भी प्रमुख फलों तथा सब्जियों के उत्पादन का स्तर तथा विश्व में 1992–93 के दौरान उनका स्थान नीचे दर्शाया गया है :

जिन्स	उत्पादन (मीटरी टन)	विश्व में स्थान
1	2	3
सेब	1168252	नौवां
केला	10459986	पहला
अंगूर	653163	उपलब्ध नहीं
नींबू वर्गीय	2979113	उपलब्ध नहीं
लीची	260943	उपलब्ध नहीं
आम	2993256	पहला
पपीता	803602	पांचवां
अन्नानास	858978	चौथा
सपोटा	423143	उपलब्ध नहीं
बन्द गोभी	4357048	चौथा
फूलगोभी	4220853	उपलब्ध नहीं
प्याज (सूखी)	5718414	दूसरा
मटर (हरी)	1491974	पांचवां
आलू	20284373	छठा
टमाटर	4849568	पांचवां

(घ) तथा (ङ) यह कहना सच नहीं है कि फलों तथा सब्जियों की उन्नत किस्मों को विकसित करने की प्रगति धीमी है। अनुसंधान प्रयासों के परिणामतः फलों की अधिक पैदावार देने वाली किस्मों/संकर किस्मों की 76 नई किस्में तथा सब्जियों की 140 किस्में विकसित की गई हैं और खेती के लिए जारी कर दी गई है ; सब्जी की 9 फसलों को 26 रोग तथा कीट प्रतिरोधी किस्मों का विकास किया गया है और उनको जारी करने की सिफारिश की गई है।

Development of fisheries in Gujarat

1685. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether there has been a considerable scope for development of marine, inland and brackish water fisheries in Gujarat State;

(b) if so, the steps taken by Government in this regard during the Eighth Plan period;

(c) the schemes under the consideration of Government and at the State level pertaining to the development of fisheries;